दुग्ध नीति

भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता देश है और लगभग 17.6 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या एवं घटती कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय ही एक मात्र ऐसा व्यवसाय है जो कृषकों को अतिरिक्त दैनिक आय का साधन उपलब्ध कराता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनवरत विकास एवं कृषि आधारित औद्योगिक ढ़ाँचा सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। यद्यपि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता प्रदेश है, किन्तु प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत में ग्यारहवाँ स्थान है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत दुग्ध उपलब्धता 301 मि0ली0 प्रतिदिन है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, किन्तु देश में नवाँ स्थान है।

प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम का संचालन प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। 58 दुग्ध संघों एवं पराग डेरी नोएडा द्वारा गठित लगभग 13,000 ग्राम्य स्तरीय दुग्ध समितियों से प्रतिदिन 6.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उपार्जित किया जा रहा है, जिससे उच्च गुणवत्ता के दुग्ध और दुग्ध उत्पाद का निर्माण कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। उपार्जित दूध की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनाये रखने के लिये ग्राम्य स्तर पर बल्क मिल्क कूलर केन्द्रों की स्थापना की गयी, जिसे विपणन हब में परिवर्तित कर ग्रामीण उपभोक्ताओं को दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराया जाता है।

परिकल्पना

दुग्ध व्यवसाय के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि तथा प्रदेश में मानव पोषण हेतु उचित दर पर स्वच्छ एवं शुद्ध दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए स्वस्थ्य समाज का निर्माण करना।

संकल्प

दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन लागत में कमी लाकर किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं कीटाणु रहित दूध उपलब्ध कराना।

भावी चुनौतियाँ

1. प्रदेश में बढ़ती दूध की मांग को पूर्ण करना।
2. दूध की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु ग्रामीण स्तर पर अवस्थापना सुविधाओं का सृजन।
3. दुग्ध उत्पादकों को उचित दुग्ध मूल्य उपलब्ध कराने हेतु पारदर्शी व्यवस्था।
4. लघु एवं सीमान्त कृषकों को दुग्ध व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आसान शर्तों पर व्यवसायिक बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना।
5. दुग्ध व्यवसाय में महिला भागीदारी को बढ़ावा देना।
6. निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन।

उद्देश्य

1. दुग्ध उत्पादकों को ग्राम्य स्तर पर ही तकनीकी निवेश सुविधाएं उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
2. दुग्ध उत्पादकों को उचित दुग्ध मूल्य भुगतान दिलाकर बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना।
3. समितियों से उपार्जित दूध को दुग्धशालाओं में प्रसंस्कृत कर स्वच्छ एवं कीटाणु रहित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना।
4. दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु पशु प्रबन्धन, प्रजनन एवं पोषण के सम्बन्ध में उत्पादकों को प्रशिक्षित करना।

रणनीति

1. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु पशु स्वास्थ्य सेवाएं, पशु आहार, चारा बीज एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराना।
2. अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं के क्रय हेतु व्यवसायिक बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना।
3. दूध की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कोल्ड चेन की स्थापना।
4. फ्लश सीजन में सरप्लस दूध को पाउडर में परिवर्तित करना ताकि ग्रीष्म माहों में उपभोक्ताओं को दूध उपलब्ध कराया जा सके।

उपरोक्त रणनीति के कियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :–

1. **स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण** – इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु प्रशिक्षण, डिटर्जेन्ट, एसेप्टिक सल्यूशन, प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण एवं बल्क मिल्क कूलर की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश के तीन जनपदों यथा लखनऊ, इलाहाबाद एवं वाराणसी में योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 202.24 लाख, रू0 240.89 लाख एवं रू0 258.66 लाख स्वीकृत है।
2. **सहकारिताओं को सहायता** – आर्थिक रूप से कमजोर दुग्ध संघों को सुदृढ़ बनाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में दुग्ध संघ मुजफ्फरनगर एवं बुलन्दशहर योजनान्तर्गत आच्छादित हैं।
3. **एकीकृत डेरी विकास योजना** – योजनान्तर्गत गैर आपरेशन फ्लड पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन, रोजगार सृजन एवं दुग्ध उपार्जन व दुग्ध विपणन में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के 26 जनपदों को आच्छादित किया गया था। वर्ष 2012–13 में जनपद शाहजहाँपुर, रामपुर एवं बरेली को रू0 1.00 करोड़ की वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी थी।

   केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उपरोक्त सभी योजनाओं को सम्मिलित करते हुए **नेशनल प्लान फार डेरी डेवलपमेन्ट** का कियान्वयन वर्तमान वित्तीय वर्ष से

प्रारम्भ किया गया है। इस योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर, अमरोहा एवं कन्नौज हेतु रू0 2682.64 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा रहा है।

4. **चारा विकास कार्यक्रम** – हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये इस योजना के अन्तर्गत उन्नत किस्म के चारा बीज का वितरण कृषकों को किया जाता है। योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार एवं 25 प्रतिशत धनराशि कार्यदायी संस्था/ दुग्ध उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 162.275 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है।

5. **नेशनल डेरी प्लान–1** – दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग को पूर्ण करने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदेश के 8 जनपदों यथा बिजनौर, मेरठ, फर्रूखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, गोण्डा, फैजाबाद एवं अम्बेडकरनगर में योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत ग्राम्य आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, पशुओं को सन्तुलित राशन उपलब्ध कराकर अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त करना तथा चारा विकास कार्यक्रम सम्मिलित है। जनपदवार स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :–

(रू0 लाख में)

क0सं0	जनपद	योजना	स्वीकृत धनराशि
1	लखनऊ	ग्राम्य आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था	119.60
		राशन बैलेन्सिंग प्रोग्राम	188.13
		चारा विकास	218.70
2	बिजनौर	ग्राम्य आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था	121.36
		चारा विकास	41.46
3	मेरठ	ग्राम्य आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था	147.67
		राशन बैलेन्सिंग प्रोग्राम	197.31
4	बाराबंकी	ग्राम्य आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था	84.89
5	गोण्डा	ग्राम्य आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था	135.73
6	फैजाबाद	ग्राम्य आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था	102.10
7	अम्बेडकरनगर	ग्राम्य आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था	110.19
8	फर्रूखाबाद	ग्राम्य आधारित दुग्ध उपार्जन व्यवस्था	93.21
		चारा विकास	110.79
	योग		1670.74

6. **गोकुल पुरस्कार** – सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में दुग्ध समितियों को सर्वाधिक दुग्ध बिक्री करने वाले दुग्ध उत्पादक को गोकुल पुरस्कार के रूप में रू0 22,000.00 नकद, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रदेश में सर्वाधिक बिक्री करने वाले तीन दुग्ध उत्पादकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार

के रूप में कमशः रू0 1.00 लाख, रू0 75,000.00 तथा रू0 50,000.00 प्रदान किया जायेगा।

अपेक्षित परिणाम

1. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
2. दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध बिक्री हेतु वर्ष पर्यन्त बाजार उपलब्ध कराना।
3. ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
4. प्रदेश में मानव पोषण हेतु स्वच्छ एवं कीटाणु रहित दूध की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
5. महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर महिला सशक्तीकरण।

कार्यपूर्ति संकेतक

1. ग्रामीण क्षेत्रों में नये दुग्ध कय केन्द्रों/ दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना।
2. सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उपार्जन की प्रगति।
3. उपभोक्ताओं को शुद्ध दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता।
4. रोजगार सृजन।